

सरकार चुकाएगी ई-पेमेंट पर ट्रांजेक्शन लागत

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नरिणय लयलल है कल जनवरी 2018 से दो सालों तक 2 हज़ार तक के डिजिटल पेमेंट पर लगने वाले मर्चेंट डलसलकलंटे रेट (MDR) का वहन वह स्वयं करेगी ।

क्या है मर्चेंट डलसलकलंटे रेट?

- मर्चेंट डलसलकलंटे रेट वह शुल्क होता है, जो बैंक कसलल भी दुकानदार या कारोबारी से कार्ड पेमेंट सेवा के लयलल लेता है । कार्ड ट्रांजेक्शन के लयलल प्वाइंटे ऑफ सेल मशीन (POS-मशीन) बैंक की ओर से लगाई जाती है ।
- बैंक द्वारा एमडीआर के तौर पर कमाई गई राशलल में से कार्ड जारी करने वाले बैंक और कुछ हलसलसा पेमेंट सर्वलसल प्रोवाइडर्स जैसे वीजा, मास्टरकार्ड को दयलल जाता है । इस शुल्क के कारण ही दुकानदार कार्ड से पेमेंट के प्रतलल अरुचलल प्रकट करते हैं । कई कारोबारी एमडीआर शुल्क का भार ग्राहकों पर डालते हैं ।
- MDR की दर RBI द्वारा तय की जाती है । पछिले दनललल ही RBI ने MDR की नई दरें लागू की थी । इसके अनुसार 20 लाख रुपए तक के सालाना कारोबार वाले छोटे कारोबारी के लयलल MDR 0.40 प्रतशत तय कयलल गया है, जो प्रतलल सौदा अधिकतम 200 रुपया तय कयलल गया है ।
- सालाना 20 लाख से ज्यादा का वयललपार करने वाले कारोबारयललल पर 0.90 प्रतशत MDR लगता है ।
- 2012 से भारतीय रज़लरव बैंक ने 2,000 रुपए के डेबलटे कार्ड भुगतान पर 0.75 फीसद एमडीआर तय कर रखा है, जबकलल 2,000 से ऊपर एक फीसद एमडीआर लयलल जाता है ।

प्रमुख बलुदु

- डेबलटे कार्ड, भीम एप तथा यूपीआई के जरयलल 2000 रुपए तक लेन-देन करने पर एमडीआर शुल्क का वहन सरकार स्वयं करेगी ।
- वर्ष 2017 में अप्रैल से सतललबर तक में केवल डेबलटे कार्ड से 2 लाख 18 हज़ार, 700 करोड़ का डिजिटल ट्रांजेक्शन हुआ है । इस दर से ये आँकड़ा 4 लाख 37 हज़ार करोड़ हो जाने की संभावना है ।
- एक अनुमान के अनुसार 2000 रुपए तक के लेन-देन के संबंघ में वतललतीय वर्ष 2018-19 में कुल 1050 करोड़ रुपए तथा वतललतीय वर्ष 2019-20 में 1,462 करोड़ रुपए की एमडीआर राशलल की प्रतललपूरतलल सरकार देश के वभिन्न बैंकों को करेगी ।
- इस छूट का मुख्य उद्देश्य केशलेस लेन-देन को बढ़ावा देना है ।